In my home State, Andhra Pradesh, at present, there are 16 KVKs in existence, covering 15 districts, as Kurnool has 2 KVKs. There has been a popular demand for opening new KVKs in six districts, namely, Khammam, Adilabad, Nizamabad, Prakasam, Cuddapah and Krishna. The farmers of these districts are being denied the services of KVKs, the new developments, and the latest knowhow in farming sector, etc. Resource crunch is cited as the reason for non-establishment of KVKs in these districts, but for the overall benefit of farmers, this has to be overcome by the Union Government.

I, therefore, earnestly request the Minister of Agriculture to direct ICAR to open new Krishi Vigyan Kendras in the districts of Khammam, Adilabad, Nizamabad, Prakasam, Cuddapah and Krishna of Andhra Pradesh, on priority basis, so that farmers of these districts can also get benefits from the KVKs. Thank you.

SHRi C. RAMACHANDRAIAH (Andhra Pradesh): Sir, I associate myself with it.

NEED TO PURCHASE KHADI CLOTHES BY CENTRAL AND STATE GOVERNMENTS FROM KHADI AND HANDLOOM SECTORS

श्री जयंती लाल बरोट (गुजरात): माननीय सभापति महोदय, मैं केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा खादी कपड़ा खरीदकर कतीन बुनकर को काम दिए जाने के संबंध में अपना विशेष उल्लेख माननीय सदन में रख रहा हूँ । पूज्य महात्मा गांधी जी ने सूत के तन्तु से समग्र भारतवासियों को एकत्रित करके स्वतंत्रता संग्राम चलाया । स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों और समाजसेवकों की पहचान खादी से होने लगी थी और समाज में लोग खादी पहनने पर गर्व करते थे, लेकिन कुछ समय से खादी क्षेत्र में कपड़े की खरीद कम हो रही है । आज कुछ पुराने गांधीवादी लोग और कुछ लोग फैशन की वजह से खादी पहनते हैं ।

सभापित महोदय, खादी की बिक्री एकदम कम हो गई है और खादी का उत्पादन जितना होता था उतना ही हो रहा है, जिससे माल बिना बिके भंडारों में पड़ा हुआ है और उस वजह से संस्थाओं ने नया उत्पादन बंद कर दिया है । इससे खादी क्षेत्र में काम करने वाले कितन और बुनकर बिना काम मिले आधी भुखमरी से पीड़ित हो रहे हैं । उनकी आमदनी में भारी कटौती आई है, जिससे खादी क्षेत्र में काम करने वाले लोग इस क्षेत्र को छोड़कर अन्य मजदूरी की ओर जा रहे हैं, लेकिन वहां भी उद्योगों में यंत्रिकरण के कारण उनको कहीं भी मजदूरी नहीं मिलती है।

सभापित महोदय, खादी क्षेत्र आरक्षित होने से इस क्षेत्र के अंदर काम करने वाले मजदूरों को आज बिना आमदनी के मरने की नौबत आ गई है । मैं इस क्षेत्र का, गुजरात खादी ग्रामोद्योग का अध्यक्ष था, इसलिए, माननीय समापति जी, मैं इस क्षेत्र के बारे में थोड़ी चिंता जताकर आपके माध्यम से माननीय केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयत्न कर रहा हूं। गुजरात सरकार में तत्कालीन मुख्य मंत्री, माननीय श्री केशुभाई पटेल थे । उस वक्त मेरी मांग पर उन्होंने यह तय किया था कि 'राज्य सरकार के सभी क्षेत्रों में जहां कपड़ा खरीदा जाता था, वहां खादी या हैंडलूम क्षेत्र से ही कपड़ा खरीदा जाए, इसके बिना किसी भी प्रकार की खरीद अमान्य की जाएगी', जिससे गुजरात के मंडारों में से राज्य सरकारों ने खादी या हैंडलूम का कपड़ा खरीदने का ऐतिहासिक निर्णय किया था और इस निर्णय से कुछ लोगों को रोजी पाने में सहायता मिली थी ।

मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि इसी तरह केन्द्रीय सरकार भी अपने सभी विभागों में और अन्य राज्य सरकारों को गुजरात की तरह खादी या हैंडलूम के कपड़े की खरीद करने का निर्णय करे तो देश के खादी क्षेत्र में काम करते कतीन बुनकर को हम कुछ न कुछ मजदूरी दे सकते हैं और इन गरीब मजदूरों की जीने में सहायता कर सकते हैं । धन्यवाद ।

SHRI BACHANI LEKHRAJ (Gujarat): Sir, I would also like to associate myself with it.

श्रीमती सदिता शारदा (गुजरात): सर, मैं भी इनको ऐसोसिएट करती हूं ।

श्री बालकवि बैरागी (मध्य प्रदेश): सभापति जी, मैं भी इनको ऐसोसिएट करता हूं ।

PRIVATE MEMBERS' (BILLS)

MR. CHAIRMAN: Dr. C. Narayana Reddy; not here. Shri P. Prabhakar Reddy; not present. Dr. T Subbarami Reddy.

THE POPULATION CONTROL BILL, 2002

DR. T. SUBBARAMI REDDY (Andhra Pradesh): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for population control through compulsory sterilization of certain persons and measures for promoting small family norm and for matters connected therewith.

The question was put and the motion was adopted.

DR. T. SUBBARAMI REDDY: Sir, I introduce the Bill.

THE COMPULSORY VOTING BILL, 2002

DR. T. SUBBARAMI REDDY (Andhra Pradesh): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for compulsory voting by the electorate in the country and for matters connected therewith.

The question was put and the motion was adopted.